जनगर्जन

वर्ष 25 अंक 2 मासिक नई दिल्ली अक्तूबर-2010 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

अयोध्या विवाद अंततः सुप्रीम कोर्ट पर अधिनिर्णय के लिये टिकी

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लखनऊ बेंच द्वारा दिया गया निर्णय अंततः सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिये भेज दिया। तीन सदस्यीय बेंच द्वारा दिया विशाल निर्णय, जिसके साथ एक असहमति पत्र भी था, जो कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये 18 वर्ष के कठिन परिक्षण के पश्चात् आया कि उसके तीनों दावेदारों को संतुष्ट नहीं किया जा सका। इस विवाद की सबसे बड़ी पार्टी ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निर्णय में कई कमियों को इंगित किया और अंत में उन्हें भारतीय मुसलमानों की तरफ से इस उक्त निर्णय को चुनौती देने का अधिकार मिल गया और संविधान के अंतर्गत निहित मौलिक तथ्यों के आधार पर निर्णय में आई खामियों को भी दूर करने और न्यायसंगत निर्णय के लिये रास्ता मिल गया। मुस्लिम बोर्ड ने आगे कहा कि न्याय और कानून के ऊपर आस्था को महत्त्व देकर इस प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की गयी है।

वहीं दूसरी तरफ अन्य मुख्य पक्ष निरोमणी अखाड़ा ने भी मूल विषयों पर उक्त निर्णय को चुनौती देते हुये सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय बना लिया है। उसे आपत्ति है कि राम जन्म भूमि के परिसर में मस्जिद बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। बंद कमरे में एक लम्बी वार्ता विनय कटियार (मस्जिद ढहाने के मुख्य आरोपी) और अखाड़ा प्रमुख महन्त भास्कर दास के बीच हुई जिसमें उन्होंने अपने हाल के निर्णय जिसके तहत बीच का रास्ता समझौते से निकालने का लिया गया था, को छोड़कर न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर दिया जिसके तहत विवादित स्थल को तीन भागों क्रमशः अखाड़ा, रामलला, सुननी वक्फ बोर्ड में विभाजित करने की बात की गयी थी। अपना विरोध जताते हुये उन्होंने कहा "इस निर्णय से राम चबुतरा और सीता रसाई पर अधिकार मिलता है परन्तु केन्द्रीय भाग तो दूसरों (रामलला विराजमान और उनके मित्रों) को दे दिया गया। मन्दिर की व्यवस्था संचालन का कार्य अखाड़ा चाहता है। जिसके कब्जे में पूरा अन्दर का भाग आया।" वे चाहते है कि मस्जिद का निर्माण विवादित स्थल से बाहर किया जाये।

न्यायालय के निर्णय जिसके अनुसार रामलला को राम जन्म भूमि का हक मिला जो केन्द्रीय डोम के अन्दर है। इस निर्णय से अखाड़ा और ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों ही नाराज हो गये। वास्तव में यही वह स्थान है जिसको लेकर संबद्ध पक्ष झगड़ रहे हैं।

अधिकांश इतिहासकारों ने न्यायालय के निर्णय पर गम्भीर चिन्ता जताई है क्योंकि इसमें पारम्परिक आस्था और विश्वास को ऐतिहासिक तथ्यों और सामग्रियों से अधिक महत्त्व दिया गया है। कोर्ट के निर्णय में राम को पौराणिक या प्रसिद्ध व्यक्तित्व न बताकर एक ऐतिहासिक व्यक्ति कहा गया हैं जिनका जन्म स्थान निर्णय में बताया गया है। इस निर्णय से रामलला असंख्य भक्तों को बहुत प्रसन्नता हुई जबकि इतिहासकारों ने इसे पूर्व आधुनिक काल (प्राचीन काल) की तरह देखा है, जब आस्था विश्वास के नाम पर धार्मिक विवाद हुआ करते थे, लोकतंत्र के नाम पर खतरनाक है। अंततः इससे धर्मान्धता, कट्टरपंथ को हवा मिलेगी जिसके कई कटु अनुभव (बाबरी मस्जिद का ढहाना जैसे) हमलोगों को भोगने पड़े है। 1992 की यह घटना आज भी हमारा पीछा करती है, क्योंकि धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध वह एक साजिश थी। उस घटना के ऊपर साम्प्रदायिक ज्वार फैलाकर भाजपा तथा अन्य साम्प्रदायिक दलों ने बहुत लाभ चुनाव में लोकसभा की सीटें जीतकर प्राप्त किया था। परन्तु आगे चलकर यह परिपाटी नहीं टिक सकी और धर्म निरपेक्ष तत्व ताकत बनकर सामने आये।

इसके बाद जो कुछ हुआ उसका एक विचारवान प्रभाव लखनऊ बेंच के निर्णय पर जनता की प्रतिक्रिया को अनुशासित करने में पड़ा। जैसे ही उक्त निर्णय की घोषणा हुई, निर्णय के पक्ष या विपक्ष में सम्मिलित समूहों ने सधी हुई प्रक्रिया दी और जीत या हार की बातों से बचते रहे। किसी भी पक्ष को देखा जाये तो यह धर्मांधता के विरुद्ध एक साकारात्मक संकेत है, यद्यपि न्यायालय के बाहर भी कुछ लोगों ने इस विवाद पर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया, परन्तु ये प्रयास विफल रहे और दोनों पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिये इच्छुक है। हम आशा करते हैं कि इस संवेदनशील विवाद के ऊपर वास्तविकता से भरा हुआ निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेगा और पक्षपात रहित निर्णय सुनने को मिलेगा जिससे बहुत लम्बे समय से चली आ रही इस समस्या का हल निकलेगा।

उच्च विकास दर के बावजूद, भूखमरी बढ़ रही है

यह बड़ा ही विरोधाभास है की भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी के प्रचार के साथ-साथ देश में भखों का भी सूचकांक तेजी से बढ़ रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत करने के साथ, अपने प्रथम लक्ष्य समावेशी विकास प्रति पूरी तरह से सुरमय हो गयी। लेकिन परिस्थिति अभी तक साफ नहीं हो पायी की विकास का परिमाप क्या है। जनता के समूहो में "आम आदमी" को लक्ष्य बनाकर सरकार ने अपने उत्तर को बड़े ही उत्साहीत ढंग से पेश किया। लेकिन कड़वा सच यह है कि देश का अमीर और अधिक अमीर हो रहा है, जबकि गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की की कीमत का सूचकांक 17 प्रतिशत को भी पार कर गया और सामान्य कीमत का सूचकांक दो अंकों के पार जा चुका है। और जनता के जिस समूह को इस बढ़ती हुई कीमत ने प्रभावित किया है वह कोई और नहीं वहीं 'आम आदमी' है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है जिससे गरीब लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वे अपने जरूरत के अनुसार अनाज की मात्रा खरीद पाने में सक्षम नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि भूखे और कुपोषितों की संख्या बढ़ती जा रही है।

इस प्रकार की खतरनाक स्थिति का उजागर हाल ही में इंटरनेशनल फूड पोलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑन द एनुअल ग्लोबल हंगर इण्डेक्स फॉर 2010 की प्रकाशित रिपोर्ट (दिनांक 11.20.2010) से हुआ, जिसके अनुसार 84 विकासशील देशों में भारत को दो पायदान नीचे खिसकाकर 67वां स्थान दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, सुडान, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया का स्थान भारत से अच्छा है। भारत का यह गीरता ग्राफ यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके पड़ोसी मुल्कों से भी काफी पीछे है जैसे श्रीलंका (32वां स्थान), पाकिस्तान (52वां), नेपाल (56वां) का स्थान है, जो गरीबी से जुझने में भारत से अच्छा कार्य कर रहे हैं। चीन 9वें स्थान पर है, ग्लोबल हंगर इण्डेक्स (जीएचआई) में छठवां स्थान है।

किसी देश का लोबल हंगर इण्डेक्स (जीएचआई) का पैमाना 100 अंकों तक दिया होता है; यदि किसी देश का अंक शून्य (0) है तो कोई भूखा नहीं है और यदि 100 है तो उस देश की स्थिति भयावह है। यह रैंकिंग तीन एक समान स्तरों पर मापा जाता है, पूरी आबादी में कुपोषण के शिकार की संख्या, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वजन, और कम वजन के कारण मृत्यु दर। भारत का आंकड़ा क्रमश: 22 प्रतिशत, 43.5 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि लोबल हंगर इण्डेक्स में भारत का अंक 24.1 है, जो कि खाद्य सुरक्षा की परिस्थिति के खतरनाक होने का संकेत देता है।

भारत की आर्थिक विकास रिपोर्ट की कहानी इस संदर्भ में बड़ी ही रोचक है। भारत की आर्थि विकास दर 2009-10 में 7.4 प्रतिशत दिखाया गया और उम्मीद जताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8.5 हो जायेगी। साधारणता आर्थिक प्रगति और भूख का स्तर एक दूसरे के विपतिरत जाते है। जिन देशों का सकल राष्ट्रीय आय या जिनका ग्लोबल न्यूट्रिशन इण्डेक्स (जीएनआई) उच्च है उनका ग्लोबल हंगर इण्डेक्स का स्कोर कम होता है, ऐसा चीन का है, जिसका जीएनआई उच्च और जीएचआई (6.0) है। लेकिन कुछ देश इस तथ्य के अपवाद भी है, जैसे दुर्भाग्य से भारत, जिसका ग्लोबल न्यूट्रीशन इण्डेक्स ऊँचा है लेकिन ऐसे में इसका ग्लोबल हंगर इण्डेक्स (24.1) है।

इस प्रकार की परिस्थिति की व्याख्या करते हुये, अर्थशास्त्री इस बात पर हुये की भारत और चीन में भूखमरी का इण्डेक्स में कमी या बढ़ोतरी में काफी अंतर है और इसका कारण इनके विकास दर। भारत का विकास दर अधिकतर सेवा क्षेत्र की जुड़ी है विशेषकर टेलिविजन और टेलिकाम में। लेकिन यह अपने कृषि क्षेत्र को लगातार अनदेखा कर रहा है जहाँ वैज्ञानिक तरीके से नहीं है तथा पिछढ़ा हुआ है। दूसरी ओर, चीन अपनी अर्थव्यव्था को सफलतापूर्वक तेजी से बढ़ा रहा है, कृषि वैज्ञानिक तरीकें से होती है तथा जो उत्पादन और सेवा क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है।

जहाँ तक भूखमरी की समस्या का संदर्भ है, यह बताया जा चुका है कि कृषि के क्षेत्र में 2-3 बार बढ़ोतरी ही भूखमरी कम कर सकता है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि हमें कृषि पर विश्वास करके आगे बढ़ना ही अच्छा रास्ता है जिससे भूखमरी की समस्या भी कम होगी।

लेकिन भारत कृषि क्षेत्र को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र में गरीब लोगों का निवेश, कृषि की वैज्ञानित पद्धति नहीं होना, कृषि के बढ़ावे के सभी कदमों को अनदेखा करना और लाखों गरीब किसानों का पलायन, कर्ज के बोझ और दु:ख से इनमें से कई को आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। भारत का कृषि विकास दर 2009-10 में चिंताजनक वित्तीय विकास 0.2 प्रतिशत था। भूख का उन्मूलन और आम आदमी के लिये भोजन की व्यवस्था की प्राथमिक आवश्यकता के कर्तव्य को सरकार भूला चुकी है। अब यह पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है। जब तक यह सरकार अपने अमीरों और कारपोरेट परस्ती नहीं छोड़ेगी तब तक आम आदमी में बढ़ती भूखमरी कम नहीं होगी।

आजाद हिन्द फौज - संयुक्त भारत के लिये संयुक्त संघर्ष

(डॉ. श्रीमती अजीत जावेद, एसोसिएट प्रोफेसर, सतयवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)

इस वर्ष 1 सितम्बर को आई.एन.ए. (इण्डियन नेशनल आर्मी) की स्थापना के 68 वर्ष हो चुके है। प्रस्तुत लेख इसी संदर्भ में इण्डियन नेशनल

आर्मी के विस्तृत इतिहास के साथ प्रकाशित हो रहा है।

भारत की आजादी के संघर्ष के इतिहास इण्डियन नेशनल आर्मी का एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उस समय जब भारत के राष्ट्रीय क्षितिज पर हर क्षेत्र में विघटनकारी शक्तियाँ सक्रिय थी तब इण्डियन नेशनल आर्मी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया था। इण्डियन नेशनल आर्मी के हथियार बन्द संघर्ष ने ब्रिटिश हुकूमत को इस बात का एहसास करने को बाध्य कर दिया था कि वे अपने शासन को चलाने के लिये भारतीय सेना की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं कर सकते थे। पूरे देश से प्राप्त सहयोग और भारतीय जनता की इण्डियन नेशनल आर्मी के प्रति सहानुभूति के अलावा ब्रिटिश–भारतीय सेना द्वारा इण्डियन नेशनल आर्मी के ट्रायल का विरोध – जैसे कुछ कारण थे जिसकी वजह से अँग्रेज सत्ता हस्तांतरण एक समझौता परस्त तरीके से करने को मजबूर हुये। इस प्रकार इण्डियन नेशनल आर्मी के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन का शीघ्र अन्त करने में भूमिका निभाई।

इण्डियन नेशनल आर्मी का गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सितम्बर 1, 1942 को हुआ था। सबसे पहले इण्डियन नेशनल आर्मी का गठन करने वालो में कैप्टेन मोहन सिंह और मोहम्मद अकरम, जो पंजाब प्रान्त के रहने वाले थे। ये दोनों ब्रिटिश भारतीय सेना से अलग हो गये थे और मलाया के जंगलों में भटक रहे थे और वहीं वे ज्ञानी प्रीतम सिंह (एक भारतीय क्रांतिकारी एवं मलाया और थाईलैण्ड के इण्डियन इण्डेपेन्डेंस लीग के महासचिव थे) जो कुछ सिखों और जापानी सेना के मेजर फुजिहारा के साथ थे, के संपर्क में आये। ज्ञानी प्रीतम सिंह ने उनसे कहा कि यदि वे अपनी मातृभूमि के लिये संघर्ष करने को तैयार हो तो जापान आपका स्वागत करेगा और हर तरफ की मदद देने को तैयार है। कैप्टन मोहन सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जापान की मदद से भारतीय सिपाहियों से संपर्क किया और द्वितीय विश्वयुद्ध में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के लिये न लड़ने के लिये उकसाया और इस युद्ध से मिले अवसर को भारत की मुक्ति के संघर्ष में लग जाने का अनुरोध किया। इस योजना का क्रियान्वयन दिसम्बर 1941 के अन्त से शुरू हो गया जो अगस्त 1942 के अंत तक चला जिसकी वजह से 45 हजार भारतीय सैनिक जो युद्ध के दौरान जापान के कैदी थे इण्डियन नेशनल आर्मी से जुड़ गये। भारत की आजादी की योजना को मूर्त रूप देने के लिये भारतीय और जापानी सेना के अधिकारियों और मलाया तथा थाईलैण्ड के नागरिकों ने एक दल को टोकियो भेजा जो जापानी हाईकमान के साथ–साथ सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारियों जो वहाँ रह रहे थे, जिनमें प्रमुख राजा महेन्द्र प्रताप और रास बिहारी बोस से संपर्क करेगा। इस दल में कैप्टेन मोहन सिंह, मोहम्मद अकरम और निरंजन सिंह गिल (जो सेना की तरफ से) एवं के.पी.के. मेनन, एन राघवन, एस.सी. गोपी, और एन.के. अय्यर (सभी नामी वकील) तथा ज्ञानी प्रीतम सिंह और स्वामी सत्यानंद पुरी (नागरिक पक्ष से) थे। जापानी दल के साथ ये लोग टोकिया के लिये 2 हवाई जहाजों से मार्च 1942 में उड़े, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, मोहम्मद अकरम, ज्ञानी प्रीतम सिंह और स्वामीसत्यानंद पुरी, का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सभी मारे गये। इस तरह इण्डियन नेशनल आर्मी के आन्दोलन में ये लोग सर्वप्रथम शहादत देने वालो में है।

टोकियो में भारतीय दल जनरल टोजो, जो जापान के प्रमुख थे, से मिला और साथ ही राजा महेन्द्र प्रताप और रास बिहारी बोस से भी मुलाकात की। रास बिहारी बोस ने कभी जापान में इण्डिया इन्डेपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और जिसका दायरा दक्षिण पूर्व एशिया के उन समस्त इलाकों तक फैल गया था जो जापान के अधीन था और छोटी संख्या में भी भारतीय वहां रहते थे। यह स्थान टोकिया ही था जहाँ इण्डियन नेशनल आर्मी की स्थापना का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि बैंकाक में सम्मेलन किया जाये और विश्व के पूर्वी क्षेत्र में फैले 30 लाख भारतीय समुदाय से सहयोग की अपील की जाये। यह सम्मेलन जून 15 से 20, 1942 में हुआ जिसमें 150 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का शुभारम्भ रास बिहारी बोस के द्वारा तिरंगा लहराकर किया गया, कैप्टेन मोहन सिंह कई घंटों तक बोलते रहे जिसमें भारत की आजादी की आवश्यकता और महत्त्व को समझाते रहे। इस सम्मेलन में तय किया गया कि इण्डियन नेशनल आर्मी के गठन में भारतीय सेना और पूर्वी एशिया के नागरिक होंगे जिसके कमाण्डर इन चीफ कैप्टेन मोहन सिंह होंगे। इस फौज का लक्ष्य भारत की आजादी के लिये संघर्ष होगा। ए.सी. चटर्जी के अनुसार जो उक्त सम्मेलन में उपस्थित थे – एक सैनिक प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्न उठाया गया कि क्या होगा जब अध्यक्ष विश्वसनीय तरीके से कार्य नहीं करेंगे या अपना उपयुक्त उत्तराधिकारी उचित तरीके से चयनित नहीं करेंगे। रास बिहारी बोस ने तुरन्त जवाब दिया कि यह पूरा आन्दोलन क्रान्किारी है और यदि अध्यक्ष अपने कर्त्तव्य के निर्वाह में असफल होता है या अविश्वसनीय हो जाता है तो उसी समय उसके अनुयायियों को उसे गोली मार देने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस हुये, मेजर जनरल मोहन सिंह इण्डियन नेशनल आर्मी के प्रमुख और रक्षा मामलों का प्रभार मिला। लफ्टिनेंट कर्नल ए.क्यू. गिलानी – सैनिक प्रशिक्षण, के.पी.के. मेनन – प्रचार एवं प्रसार का भार दिया गया। एन. राघवन को इण्डिपेण्डेंस लीग के संगठन का कार्य और निरंजन सिंह गिल को आजाद हिन्द फौज का प्रमुख सलाहकार बनाया गया। गाँधी ब्रिगेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल एम.जेड. कियानी, नेहरू ब्रिगेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल और आजाद ब्रिगेड का नेतृत्व कर्नल प्रकाश चन्द को सुपुर्द किया गया। आजाद हिन्द फौज मुसलमानों के साथ साम्प्रदायिक नहीं था क्योंकि फौज के हर स्तर के अधिकारियों में मुसलमानों को प्रमुखता दी गयी थी। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव और पारित हुआ जिसमें इण्डियन नेशनल आर्मी के आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिये पूर्वी एशिया से सुभाष चन्द्र बोस को निमन्त्रण भेजा गया।

बैंकाक सम्मेलन के समापन के बाद सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में चले गये और इण्डिया इंडिपेंडेंस लीग को स्थापित करने, कोष वृद्धि और नए सदस्यों की भर्ती में लग गए। इण्डियन नेशनल आर्मी ने सिंगापुर में माउंट प्लीजांट में अपना मुख्यालय खोला जबकि यह वह स्थान था जहाँ कोई भारतीय या एशियाई मूल का व्यक्ति पैदल चल भी नहीं सकता था। इण्डियन नेशनल आर्मी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाहर रह रहे भारतीयों को जगाना आवश्यक था और इस उद्देश्य के लिए पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं। जैसे - अँग्रेजी में वायस ऑफ इण्डिया और आजाद हिन्द, हिन्दुस्तानी में आवाज हिंद और आजाद हिन्द और तमिल में स्वतंत्र भारत थे। ये सभी प्रकाशन सिंगापुर से प्रकाशित होते थे तथा बहुत लोकप्रिय थे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लिए एक ट्रेंनिंग स्कूल खुला और लेफ्टिनेंट कर्नल शाह नवाज को उसका प्रथम कमांडेंट बनाया गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर की देखरेख में एक सैनिक प्रशिक्षण का संस्थान संचालित हुआ जिसमें स्वेच्छा से आए नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा' कौमी तराना तय हुआ। आजाद हिन्द फौज की पहली परेड अगस्त 1942 में हुई, तिरंगा लहराया गया और कैप्टन मोहन सिंह ने क्रांतिकारी भाषण दिया। कुछ अंतराल के बाद इण्डियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों और जापानियों के बीच मतभेद उभरने लगे। कैप्टन मोहन सिंह चाहते थे कि जापानी भारती की आजादी के तथ्य को तुरन्त समझें और स्वीकार करें जबकि जापानी इस तथ्य पर उदासीन रवैया अपनाएं हुए थे। मोहन सिंह जापानी रवैये के प्रति संदेह करने लगे और 21 दिसम्बर 1942 को उन्होंने आजाद हिंद फौज को भंग कर देने की घोषणा कर दिया।

एक बार पुन: रास बिहारी बोस की मदद से 15 फरवरी 1943 को आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल भोसले को मिलिट्री ब्यूरो का निदेशक बनाया गया। कर्नल शाह नवाज को जनरल स्टॉफ का प्रमुख बनाया गया। मेजर पी. के. सहगल को मिलिट्री सचिव और मेजर हबीबुर रहमान को आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडेंड बनाया गया। मेजर माता-उल-मुल्क (लेफ्टिनेंट कर्नल बुरहान उद्दीन के भाई) को रिइनफोर्समेंट कमांडेंट, मेजर ए.डी. जहाँगीर को इनलाइटमेंट एण्ड कल्चर का प्रभार, लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर को रिक्रूटमेंटी (भर्ती) विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। जिन्हें साइगोन रेडियो से देशभक्ति से ओत-प्रोत रोमांचक कार्यक्रम (विशेष रूप से पंजाबी में) प्रस्तुत करने से अच्छी खासी लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। नीति-निर्धारण के कार्य के अतिरिक्त पूरी सेना का नियंत्रण लेफ्टिनेंट कर्नल एम.जेडत्र कियानी के तहत था। यह वह संगठन था जिसने इण्डियन नेशनल आर्मी को एकजुट रखा और बर्लिन से छ: माह के बाद सुभाष चन्द्र बोस के आगमन तक सुरक्षित रखा।

राजनीति में बोस, सी.आर. दास के शिष्य थे। वे धर्म निरपेक्ष और विदेशी शासन के समझौता विहीन परस्त शत्रु थे। वह ग्यारह बार जेल गए थे। गाँधी और नेहरू की तरह उन्हें कोई सुविधा या आराम जैसा लाभ नहीं मिलता था, बल्कि जेल में उन्हें प्रताड़ना मिली और मार पड़ी थी एक बार उन्हें मांडले जेल में रखा गया था। कांग्रेस के भीतर वे वाम गुट से सम्बद्ध नहीं थे। फिर भी गाँधी ने बोस की तुलना में नेहरू को चुना। बोस अपने स्नेहिल व्यक्तित्व से नेहरू पर भारी थे और गाँधी से वैचारिक मतभेद भी थे। इसके बावजूद 1939 में गाँधी के विरोध के बावजूद बोस कांग्रेस के सभापति के लिए खड़े हुए और चयनित हुए और इस तरह वे गाँधी के कोप भाजन बने। उन्होंने गाँधी के समर्थित उम्मीदवार डॉ. सीतारम्मैया को हराया। जीतने के बावजूद बोस को इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि गाँधी और उनके समर्थक नाखुश थे। उन्हें कांग्रेस से निलम्बित भी कर दिया गया था। एक गैर चयनित कांग्रेसी बाबू राजेन्द्र प्रसाद कांग्रेस के सभापति नियुक्त किये गये। जब द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ, ब्रिटिश हुकूमत ने सुभाष को जेल में डाल दिया और बाद में नजरबंद कर दिया गया क्योंकि युद्ध के ब्रिटिश कारणों का वे विरोध करते थे। भारती की ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति की विविभिषा ने उन्हें एक्सिस शक्तियों (गैर अमेरिकी शक्तियों) से सहयोग लेने की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने जनवरी 1941 में कलकत्ता से पलायन कर अकबर शाह, मोहम्मद शाह, अबाद खान और भगत राम तलवार की मदद से पेशावर और काबुल होतु हुए मार्च 1941 में बर्लिन पहुँचने में सफल हुये। बर्लिन में उन्होंने फ्री इण्डिया सेंटर की स्थापना और इण्डियन लिजियन की रचना की, जिसमें भारतीय युद्ध बंदियों में से 45000 सैनिक जुड़े। 2 नवंबर 1941 को अधिकारिक रूप से फ्री इण्डिया सेंटर की मीटिंग हुई जिसमें उन्हें 'नेताजी' के नाम से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में 'जय हिंद' कहा गया और जन-गण-मन को राष्ट्र गान के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्र भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में सबसे अधिक बोले जाने वाली 'हिन्दुस्तानी' को स्वीकार किया गया। वर्ष के अंत में आजाद हिन्द रेडियों ने कार्य करना शुरू कर दिया और आजाद हिन्द नाम से एक द्विभाषीय पत्र नियमित रूप से प्रकाशित होने लगा। बोस हिटलर और मुसोलिन दोनों से मिले परन्तु जर्मनी द्वारा रसिया पर किये गये आक्रमण पर विरोधात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जापानियों की महत्त्वपूर्ण सफलता को सुनकर उत्साहित हो उठे। उन्होंने आई.एन.ए. का नेतृत्व करने के लिये हामी भरी और आबिद हसन (इण्डिया इण्डिपेंडेंट लीग, जर्मनी) के साथ जापान की ओर बढ़े और अपना एक मात्र लक्ष्य घोषित किया। बोस आबिद हसन के साथ एक जर्मन पनडुब्बी के द्वारा जापान पहुँचे।

सुभाष चन्द्र बोस के आगमन के बाद जापानी प्रमुख तोजो ने उन्हें जापानी संसद (डाईट) में बुलाया, जहाँ जापानी प्रमुख ने भारत की आजादी के मामले पर पूर्ण रूप से समर्थन देने की घोषणा अधिकारिक रूप से की। वहीं से टोक्यो रेडियो के द्वारा बोस ने भारत की पूर्वी सीमा से ब्रिटिश हुकूमत पर आक्रमण करने की दृढ़ इच्छा व्यक्त की। विदेशों में रहने वाले भारतीय खुशी से उछल पड़े और इसमें सहयोग के लिये कूद पड़े।

2 जुलाई 1943 को बोस सिंगापुर पहुँचे जहां उनका स्वागत भविष्य निर्माता के रूप में भव्य तरीके से किया गया। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इण्डिया इण्डिपेण्डेंस लीग और इण्डियन नेशनल आर्मी दोनों का नेतृत्व बोस को सौंपा। उक्त दोनों संगठनों का अस्तित्व कैप्टेन मोहन सिंह के द्वारा भंग किये जाने के बावजूद मौजूद था। 5 जुलाई 1943 को इण्डियन नेशनल आर्मी के सैनिकों द्वारा पूरी तरह से सैनिक लिबास में सलामी स्वीकार

की। उन्होंने सैनिकों को सम्बोधित किया।

"आज का दिन मेरे लिये सबसे अधिक गर्व का दिन है। आज पूरी दुनिया के सामने सम्मान पूर्वक एक आद्वीतीय अवसर मुझे मिला है। जिसके अनुसार मैं घोषणा करता हूँ की भारत की मुक्ति की सेना अस्तित्व में आ चुकी है। साथियों अब आप के युद्ध का नारा 'दिल्ली चलो'! होना चाहिये। मैं नहीं जानता की स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से व्यक्तिगत रूप से कौन बचेगा, परन्तु निश्चित रूप से यह जानता हूँ कि विजय हमारी ही होगी और तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा जब तक पुरानी दिल्ली के लालकिले में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कब्र पर हमारे बचे हुये बहादुर सैनिकों के जीत की परेड वहां नहीं हो जाती है।"

26 अगस्त 1943 को सुभाष चन्द्र बोस इण्डियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च कमाण्डर चुने गये और उनहोंने इसका नाम बदलकर आजाद हिन्द फौज कर दिया। उन्होंने निम्नलिखित आदेश पारित किये :

..... जब हम खड़े हो, आजाद हिन्द फौज ग्रेनाईट की दिवार की तरफ हो, जब हम मार्च करें तो आजाद हिन्द फौज एक स्टीम रोलर की तरह हो। हमारे होठों पर 'दिल्ली चलो'! का नारा होना चाहिये हम संघर्ष जारी रखे जब तक दिल्ली स्थित वायसराय के घर पर तिरंगा न लहरा जाये और आजाद हिन्द फौज पुराने लालकिले में जीत की परेड न कर ले ....।

इसके बाद मलाया, पेनांग और बैंकाक के बहुत स्थलों की उन्होंने यात्रा की और अपने इस संदेश को प्रचारित किया। साथ ही मातृभूमि की रक्षा के लिये भारी भरकम धनराशि भी एकत्रित किया। ऐसे ही किसी सभा में बोस की माला 5 लाख डॉलर में बिकी। बोस ने दक्षिण एशिया में जनता से 30 मिलियन (3 करोड़) की मांग की जबकि वहाँ से भारतीयों ने उन्हें इसकी दुगुनी राशि दी। बर्मा में मिस्टर हबीब ने जमीन, घर और आभूषण जिनकी कीमत 1 करोड़ रूपये से ज्यादा थी, सब कुछ समर्पित कर दिया और अपना जीवन भी बोस की इच्छा पर सौंप दिया। श्री रामदास खन्ना ने अपनी सभी कुछ चल, अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत एक मिलियन डॉलर थी, समर्पित कर दिया और अपना शेष जीन इस कार्य में लगा दिया। श्री बशीर ने आधा मिलियन, श्री निजामी ने आधा मिलियन, श्री माधा ने आधा मिलियन श्री पिचाई (एक स्थानीय मुस्लिम व्यापारी) ने अपने तीन छापाखाने और सम्पूर्ण जायदाद समर्पित कर दिया। इन सभी को नेताजी ने अपने हाथों से सेवक-ए-हिन्द का मेडल पहनाया। वहाँ बोस ने नौजवानों का आह्वान किया: "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा"। स्वतंत्र भारत के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर की मजार पर बोस गये और उन्होंने उस महान आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया।

सितम्बर माह में एक नई ब्रिगेड जिसे गोरिल्ला रेजिमेंट कहा गया, का गठन हुआ, जिसके कमाण्डर शाहनवाज नियुक्त हुये। सैनिकों ने स्वयं इसे सुभाष ब्रिगेड नाम से पुकारा। बोस के कमाण्ड संभालने के समय तक आजाद हिन्द फौज में सैनिकों की संख्या 60,000 से आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने अनेक महिलाओं के समूहों को सम्बोधित किया जिसमें देश की सेवा के लिये उन्हें आगे आने का न्यौता दिया। लक्ष्मी सहगल के अनुसार (पूर्व में स्वामीनाथन) के लेख के अनुसार "उन्होंने हमें स्मरण कराया, 'झांसी की रानी लक्ष्मी बाई और अन्य बहादुर भारतीय नारियों जिन्होंने हथियार बन्द तरीके से ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया था और आगे उन्होंने बंगाल की युवतियों की चर्चा करते हुये शांति, कोमिला की सुनीती, चिटगांव की कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेडर के बारे में बताया ..., उनके सम्बोधन के बीच में एक दम शांति के साथ बिजली की कड़कड़ाहट की तरह तालियों की गूँज उठ रही थी और हजारों नारियां मंच की तरफ दौड़ी। वे स्वेच्छया अपना जीवन देश की आजादी के लिये समर्पि करने के उत्साह से भरी थी। 23 अक्तूबर 1943 को कैप्टेन लक्ष्मी स्वामीनाथन (एक डॉक्टर) के नेतृत्व में एक महिला रेजिमेंट का गठन हुआ उन्होंने अपनी आकर्षक डाक्टरी पेशा छोड़कर अपनी समृद्धशाली डिस्पेंसरी को आजाद हिन्द फौज अस्पताल के रूप में समर्पित कर दिया। इस रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के नाम पर रखा गया। महिलाओं की एक नर्सिंग टीम का गठन किया गया जिसका नाम चांद बीबी रखा गया। 21 अक्तूबर 1943 को सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद भारत के अस्थाई सरकार की घोषणा की और उसके सर्वोच्च तथा आजाद हिन्द फौज के सुप्रीम कमाण्डर स्वयं को घोषित किया। उनके मंत्रीमण्डल में थे - कैप्टेन लक्ष्मी स्वामीनाथन, कर्नल ए.सी. चटर्जी, श्री एस.ए. अय्यर, लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद, लेफ्टिनेंट कर्नल एन.एस. भगत, लेफ्टिनेंट कर्नल एम.जेड. कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल ए.डी. लोगांथन, लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर, शाहनवाज खान, मैसर्स ए.एम. सहाय, ए. अलप्पा, ए.एन. सरकार, लेफ्टिनेंट कर्नल ए.एन. राजु, देवनाथ दास, करीम गनी, डी.एम. खान, जे. झीवी और ईश्वर सिंह। रास बिहारी बोस को बशीर अहमद को सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद निष्ठा की शपथ लेने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सुभाष ने शपथ लेते हुये कहा: "मैं सुभाष चन्द्र बोस भारत की मुक्ति और इसके 38 करोड़ लोगों के लिये ईश्वर के नाम पर इस पवित्र शपथ को लेता हूँ कि मैं अपने अंतिम सांस तक आजादी के इस पवित्र युद्ध को जारी रखूंगा ...। कर्नल ए.सी. चटर्जी के अनुसार "इस क्षण सुभाष भावुक हो गये थे उनकी आंखें जोशीली और आंसूओं से भरी थी और गला रूंधा हुआ था।"

एक्सीस शक्तियाँ और उसके अधीन मुल्कों ने इस अस्थायी सरकार को तुरन्त मान्यता प्रदान की जापानियों ने सुभाष को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया। नवम्बर 1943 को बोस इन द्वीपों पर मेजर हसन और सहाय के साथ गये। इन द्वीपों का नया नामकरण शहीद एवं स्वराज द्वीप किया और लेफ्टिनेंट कर्नल लोगांथन को मुख्य आयुक्त इन द्वीपों का नियुक्त किया और मेजर अल्वी को उनका उपायुक्त नियुक्त किया।

भारतीय, चाहे वह किसी भी जाति का हो, मजहब या धर्म का हो वे अपने प्रेरक नेतृत्व के प्रति एकजुट हो जाते है। इण्डियन नेशनल आर्मी की

स्थापना के आरम्भ में कुछ मुस्लिमों ने बन्दे मातरम गाने पर बैन लगाने की मांग की क्योंकि इसके अंतिम दो पद मुस्लिम विरोधी थे। मामला टाल दिया गया। इण्डियन नेशनल आर्मी पदभार संभालने के बाद, बोस ने, एकता में बाधा बन रही किसी भी प्रकार की दुविधा को समाप्त करने के लिये एक नया गीत सुझाया जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। एक हुसैन नामक मुस्लिम द्वारा रचित एक गीत, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे.., को आखिरकार, सहमति दे गयी। जिसे हृदय से सभी ने स्वीकार किया और यह अत्यंत ही प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रीय अभिवादन बंदे मातरम से जय हिन्द में बदल दिया गया। बोस ने यह भी निर्णय लिया की तिरंगा झण्डे में बदलाव किया जाना चाहिये और वह बिना चरखे के होना चाहिये। इस प्रकार दो समुदायों को पुर्ण रूप से एकीकृत किया गया और इनके बीच में कोई भेदभाव, विरोध, दुश्मनी या संदेह नहीं था।

........शेष अगले अंक में.......

हिन्दी अनुवाद - प्रभाशंकर मिश्र, राष्ट्रीय सह-संयोजक जन संग्राम मोर्चा (जन संगठन)।

जननायक पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी -

स्वतंत्रता संग्राम तथा समझौता विरोधी आन्दोलन के महान योद्धा

जन नायक पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी प्रखर किसान नेता, समाज सुधारक तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कट्टर अनुयायी थे। इस बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी महानचिंतक की जीवन यात्रा को एक छोटे से लेख के जरिये अभिव्यक्त करना गागर में सागर भरने जैसा प्रयास है।

पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी का जन्म 5 अक्टूबर 1899 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के बांगरमऊ, माता श्रीमति कौशल्या देवी के द्वितीयप पुत्र के रूप में हुआ। इनके पिता का नाम श्री गया प्रसाद त्रिपाठी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गाँव में ही हुई। इन्होंने राजकीय इन्टर कॉलेज सीतापुर से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा उतीर्ण किया। अध्ययन के दरम्यान ही इनका विवाह 1918 में कृष्णा कुमारी के साथ हो गया। दाम्पत्य जीवन में बँध जाने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी। सेन्ट्रल हिन्दु विश्व विद्यालय बनारस से इन्होंने इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया और आगे की पढ़ाई के लिये बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय में दाखिलाफ लिया। जहाँ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के सान्निध्य में रहकर अध्ययन करने का इन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ।

ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ भारतवर्ष में सर्वत्र आग फैल चुकी थी। महात्मा गाँधी का भारत के कोने-कोने में भ्रमण जारी था। गाँधी जी का इसी क्रम में बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय में भी आगमन हुआ। त्रिपाठी जी ने गाँधी जी का गर्म जोशी से स्वागत किया एवं उनसे प्रभावित होकर उनके आह्वान पर मातृभूमि के लिये मुक्ति आन्दोलन में पढ़ाई लिखाई छोड़कर कूद पड़े और देश सेवा का व्रत लिया। सामाजिक कार्यों में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीड़ित एवं रुग्ण मानवता की सेवा के उद्देश्य से इन्होंने बांगरमऊ में तिलक औषद्यालय की स्थापना की। इस अवधि में इन्होंने 'स्वराज्य' साप्ताहिक समाचार पत्र का भी सम्पादन किया। 'स्वराज्य' शोषित पीड़ित, दबे, कुचले व्यक्तियों के कष्टों का एवं जनता में देश प्रेम प्रवाहित करने वाला समाचार पत्र बन गया।

महात्मा पं० मदन मोहन मालवीय के सुझाव पर पुन: विश्वम्भर दयाल ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। कुशाग्र पतिभा के धनी त्रिपाठी जी ने बी.ए. की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इन्हें इतिहास विषय में एम.ए. में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उस समय विश्व विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर छात्र को शोध हेतु लंदन में अध्ययन करने का स्वत: अधिकार प्राप्त हो जाता था। लेकिन उन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय रूप से जुड़ने का संकल्प ग्रहण कर लिया था इसलिये शोध अध्ययन का सुअवसर त्याग दिया। साथ-साथ उन्होंने एल.एल.बी. की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया।

1927 में उन्होंने उन्नाव में वकालत शुरू किया। वे शोषित, पीड़ित जनता की मुकद्दमों की पैरवी अल्प शुल्क में किया करते थे। अन्याय एवं जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना उनकी सहज स्वभाव था।

उन्नाव पुलिस ने उन पर अभियुक्त छीनने का झूठा मुकद्दमा दर्ज करा दिया।

इस समय संपूर्ण देश में अँग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आन्दोलन की लहर सर्वत्र फैल चुकी थी। उन्होंने इस आन्दोलन का उन्नाव में नेतृत्व किया और 26 जनवरी 1930 को स्थानीय लोकसेवा आश्रम पर तिरंगा झण्डा फहरा दिया।

महात्मा गाँधी के आह्वान पर इन्होंने नमक आन्दोलन में भाग लिया और 2 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिये गये एवं छ: माह की जेल की सजा हुई और उन्नाव जेल में डाल दिये गये।

विदेशी वस्त्र बहिष्कार शराबबंदी आन्दोलन का नेतृत्व करने में अभियोग में इन्हें पुन: 14 नवम्बर 1930 को गिरफ्तार कर फैजाबाद जेल भेज दिया गया जहाँ इन्होंने एक वर्ष की सजा काटी।

अँग्रेजों ने पुलिस के द्वारा पिपरी गाँव को लुटवा लिया जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठायी। जवाहर लाल नेहरू को बुलाकर भारी आम सभा आयोजित किया एवं इसकी आवाज लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से उठवाया जिसके अभियोग में ये पुन: गिरफ्तार कर लिये गये। इन्हें पुन: जेल अधिकारियों से संघर्ष के कारण फैजाबाद जेल में ही दर्जा देकर क्रुर जेल यातना दिया गया एवं एक वर्ष तक जेल में रखा गया।

जेल से छूटने के बाद ये प्रांतीय कांग्रेस कमिटि में महत्वपूर्ण पद पर रहे एवं किसान आन्दोलन का नेतृत्व किया। इन्हें उत्तेजक भाषण देने के आरोप में पुन: उन्नाव में गिरफ्तार कर लिया गया।

पं० त्रिपाठी 1937 में सफीपुर उन्नाव से एम.एल.सी. विधायक चुने गये तब इन्होंने वकालत छोड़ दिया। इन्हें किसानों के हित के लिये कानून बनाने की विधान सभा की कमिटि में सदस्य नियुक्त किया गया।

1 मार्च 1938 में पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी के नेतृत्व में उन्नाव से एक लाख किसानों का ऐतिहासिक लखनऊ मार्च किया गया जिसमें जमींदारी उन्मूलन एवं किसानों का उनका उचित हक दिलाना शामिल था। इस ऐतिहासिक किसान मार्च की संपूर्ण देश के साथ-साथ इंग्लैण्ड में भी जोरदार चर्चा हुई और मजबूर होकर सरकार को जमींदारी उन्मुलन विधेयक लाना पड़ा। इस उल्लेखनीय ऐतिहासिक आन्दोलन के लिये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने उन्हें उन्नाव का बेताज बादशाह की उपाधिी दी।

राष्ट्रीय राजनैतिक परिदृष्य पर इसके बाद पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गहन संपर्क में आये।

13, 14 एवं 15 मई 1938 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रांतीय युवक सम्मेलन में भाग लेने उन्नाव आये। फिर लाहौर में ऐतिहासिक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन भाषण नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने दिया। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 8 लाख नौजवानों ने भाग लिया।

1939 में उन्हें राजद्रोह एवं सरकार विरोधी भाषण देने के अभियोग में छ: वर्ष की कठोर कारवास की सजा दी गई और राय बरेली एवं फैजाबाद जेलों में डाल दिया गया। इस अवधि में उन्होंने जेल यात्रा के दौरान 'कर्मवीर लेनिन तथा भूमि व्यवस्था' नामक दो पुस्तकें लिखी।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष से त्यागपत्र देने के बाद समझौता विरोधी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये एक राजनैतिक दल की स्थापना की जरूरत महसूस किये जाने पर नेताजी के साथ पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी की भी फारवर्ड ब्लॉक संस्थापकों में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नेताजी के स्वदेश छोड़ने के बाद फारवर्ड ब्लॉक का 1946 के समय कार्यसमिति में वरिष्ठ संस्थापक अध्यक्ष, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अध्यक्ष सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर, उपाध्यक्ष आर.एस. रुईकर एवं पं० शीलभद्र याजी, महामंत्री हरि विष्णु कामथ और मंत्री के रूप में मुकुन्द लाल सरकार, पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी, प्रो० विदेश कुलकर्णी तथा राजकुमार चिती थे।

बहुरमुखी प्रतिभा के धनी, महान स्वतन्त्रता सेनानी, शिक्षाविद् प्रख्यात किसान नेता, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अनन्य सहयोगी पं० विश्वम्भर दियालु त्रिपाठी का संपूर्ण जीवन देशभक्तिपूर्ण समझौता विरोधी आन्दोलन से ओत-प्रोत रहा।

आजादी के बाद जब देश में पहली कांग्रेस सरकार पं० जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में बनी तब नेताजी के प्रमुख अनुयायियों को एक एक करके पंडित नेहरू ने कांग्रेस में यह समझाकर लाया कि जब कांग्रेस ने अपने आवाडी सम्मेलन में 'समाजवादी ढाँचे के समाज के निमार्ण का प्रस्ताव ग्रहण कर लिया है' तब फारवर्ड ब्लॉक को अलग राजनैतिक दल के रूप में अस्तित्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होता है। पं० नेहरू के इस झाँसे में उस समय पं० शीलभद्र याजी, जनरल शाहनवाज, पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी जैसे तपे-तपाये, जलाये नेता कांग्रेस में आ गये। बाद में उन्होंने जीवन पर्यन्त महसूस किया कि कांग्रेस की समझौता परस्त नीतियों से नये भारत के निर्माण की बात तो दूर भारत की प्रगति भी नहीं हो सकती है। भारत का पुनर्निर्माण में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा बताये गये रास्ते पर चलकर ही हो सकता है।

आज जब पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी की जन्म शताब्दी मनायी जा रही है तब हमारी उस ममान आत्मा के प्रति यह विनम्र श्रद्धांजलि होगी कि नेताजी द्वारा बताये गये सिद्धांतों एवं आदर्शों पर चलकर समझौता विरोधी अधुरे संग्राम को तेज कर हम नेताजी के सपनों का भारत पुनर्निर्माण का संकल्प ग्रहण करें।

पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी का असमायिक निधन 18 नवम्बर 1957 में हो गया। भले ही वे भौतिक शरीर के रूप में हमारे बीच आज नहीं है लेकिन भारत के स्वाधीनता आन्दोलन, नेताजी के समझौता विरोधी देशभक्तिपूर्ण संग्राम में उनकी उल्लेखनीय भूमिका एवं अमूल्य योगदान को भूलाया नहीं जा सकता है।

....साथी देवब्रत बिश्वास, महासचिव
अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

उन्नाव में जननायक पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी जयन्ती आयोजित

उन्नाव, उ.प्र.: प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 अक्तबूर 2010 को उन्नाव जनपद ने अपने जननायक प्रान्त गौरव महान क्रान्तिकारी पंडित विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी जी की जयन्ती मनाई। जिले की जनता त्रिपाठी जयन्ती प्रत्येक वर्ष बड़ी ही धूमधाम से मनाती है, किन्तु इस वर्ष की जयन्ती इस प्रकार से मनाई गई की इस जयन्ती समारोह का राजनैतिक और सामाजिक महत्त्व कुछ अधिक ही बढ़ गया। संयोग की बात है कि इस वर्ष जिलमें की त्रिपाठी स्मारक समिति ने स्थानीय नेताओं के अतिरिक्त अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के महामंत्री श्री देवब्रत बिश्वास जी भी उपस्थित थे। डॉ. रश्मि दीक्षित जी (शहीदे-आजम त्रिपाठी जी की सुपुत्री) के आमन्त्रण पर साथी देवब्रत बिश्वास जी पूरे कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे।

इस अवसर डॉ. रश्मि दीक्षित जी ने कहा कि श्री देवब्रत जी के आगम ने अनेक ऐतिहासिक स्मृत्तियों को सजीव कर दिया। श्री बिश्वास जी नेताजी के विचारों के अनुसार राष्ट्र गति देने के लिए तत्पर है और पं. विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी जी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के दाहिने हाथ थे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री देवब्रत बिश्वास जी 5 अक्तूबर 2010 को प्रातः 5.30 बजे उन्नाव पधारे। उनका यह आगमन इस वर्ष त्रिपाठी जयन्ती समारोह एक बहुत बड़ा संगठनात्मक और वैचारिक प्रमाण छोड़ गया। जन्म जयन्ती का कार्यक्रम लोक सेवाश्रम के उस परिसर पर श्रद्धांजलि देने से प्रारम्भ हुआ जहाँ पं. त्रिपाठी जी की अस्थि अवशेषों को रखा गया था। उनके अनुज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. बालगंगाधर त्रिपाठी द्वारा निर्मित अपूर्ण स्तम्भ पर श्री देवब्रत जी ने माल्यार्पण किया। श्री बिश्वास जी स्व० पं. बाल गंगाधर त्रिपाठी के परिवार से भी उनके घर जाकर मिले।

लोकसेवाश्रम के बाद श्री देवब्रत बिश्वास जी पं. विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी राजकीय जिला पुस्तकालय गए। वहाँ पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. मृदुला पंडित ने उन्हें उत्तरीय एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। श्री बिश्वास ने नेताजी द्वारा सम्पादित फारवर्ड ब्लॉक पत्रिका के दुर्लभ अंक व पुस्तकें डॉ. मृदुला पंडित को देने की बात कही।

पं. विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी राजकीय पुस्तकालय के बाद श्री बिश्वास जी जनपद के सबसे बड़े कॉलेज दयानन्द सुभाष नेशनल कॉलेज पहुँचे जहाँ त्रिपाठी जी का जन्म दिवस संस्थापक दिवस के रूप में मनाया गया। कॉलेज परिसर में स्थापित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एवं पं. विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात् सरस्वती पेक्षागृह में कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। श्री देवब्रत बिश्वास ने कहा कि डी.एस.एन. कॉलेज में एक बड़ा इतिहास छिपा है क्योंकि इतिहास के पुरोधा त्रिपाठी जी ने इसकी नींव रखी थी। यह कॉलेज देश के म से कम एक पं. विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी दे। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. अवध राम ने कहा कि मेरे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों के अन्तर्गत त्रिपाठी जी से अधिक अनुभवों के अंतर्गत त्रिपाठी जी से अधिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार में समर्पित व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अन्त में जय हिन्द कॉलेज का युवा वर्ग विशेषतः विद्यार्थी वर्ग श्री बिश्वास के उद्‌बोधन से अत्यधिक प्रभावित हुआ।

अब तक दिन के एक बज चुके थे श्री देवब्रत बिश्वास को पंडित विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी स्मारक समिति द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेना था। वहाँ नगरपालिका अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता की अध्यक्षता में सभा प्रारम्भ हो चुकी थी और मैगासेसे पुरस्कार प्राप्त प्रखर समाज सेवी श्री संदीप पाण्डेय का वक्तव्य हो चुका था क्योंकि उन्हें अन्यत्र किसी कार्यक्रम में जाना था। सभास्थल पर पहुँचते ही उपस्थित जनसमुदाय ने श्री देवब्रत बिश्वास का जोश भरा स्वागत किया। इस अवसर पर राज्य सभा सदस्य श्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, श्री अशोक सिंह 'बेबी', श्री पंकज गुप्ता तथा डॉ. रश्मि दीक्षित ने त्रिपाठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनेक बताए हुए जनसेवा के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। सारगर्भित भाषण देते हुए श्री देवब्रत बिश्वास ने उन्नाव की धरती का नमन किया जहाँ देशभक्त क्रान्तिकारियों ने नेता जी और त्रिपाठी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम का क्रान्तिकारी बिगुल बजाने का संकल्प लिया था। श्री देवब्रत बिश्वास ने इतिहास के न पृष्ठों को भी खोला जिनके आधार पर 1942 की क्रान्ति मे स्वतंत्रता संग्राम में आहुति दी गयी थी। श्री बिश्वास के ओजपूर्ण उद्‌बोधन से उपस्थित जनसमूह बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में पहली बार जयन्ती समारोह में उन्नाव और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के निकट सम्बन्धों की विशद जानकारी प्राप्त हुई।

श्री देवब्रत बिश्वास की उपस्थिति का लाभ उठाते हुये स्थानीय पत्रकारों ने भी उनसे मिलकर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर डाला। श्री बिश्वास ने उत्साही नवयुवक पत्रकारों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुये उन्होंने फारवर्ड ब्लॉक के वैचारिक पक्ष को स्पष्ट किया। वार्ता में उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाएं आम आदमी के लिए नहीं बनती। वे केवल कारपोरेट सेक्टर के लिए बनती है, जिससे अमीर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें त्रिपाठी जी का सपना पूरा करना है। त्रिपाठी जी ने 1 मार्च 1938 को एक लाख किसानों के साथ लखनऊ तक पैदल मार्च करके उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। परिवर्तन का आगाज जनता ही करती है। नेताजी जी के बताए पाँच आधारभूत बातों पर समाज टिका हुआ है, वे हैं – समानता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अनुशासन और प्रेम। बंदूक के जरिये आजादी नहीं मिल सकती। कश्मीर के लोग इकोनॉमी पैकेज नहीं, मानवता, प्रेम और भाईचारा चाहते हैं। यदि कश्मीर के 10 हजार लोगों को भारत के हर प्रान्त में नौकरी दे दी जाए तो वे हर जगह प्यार और भाईचारा का संदेश दे सकते हैं। कामनवेल्थ गेम में सरकार 70 हजारा करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यदि इसका 10 प्रतिशत भी प्रदेश के विकास पर व्यय कर दिया जाये तो सूरत बदल जाएगी। इस अवसर पर पत्रकारों के अतिरिक्त डी.एस.एन. कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री रामकिशोर, डॉ. रश्मि दीक्षित, श्री सुधीर शुक्ल तथा अनेक शिक्षक उपस्थित थे।

अब तक शाम के पाँच बज चुके थे। अत्यधिक व्यस्तता के कारण श्री देवब्रत बिश्वास को मध्यान्ह भोजन के लिए भी समय नहीं मिल सका था। अतः शीघ्रतापूर्वक भोजन से निवृत्त होकर श्री राम किशोर महामंत्री उत्तर प्रदेश फारवपर्ड ब्लॉक, डॉ. रश्मि दीक्षित, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री सुधीर

शुक्ला तथा त्रिपाठी जी के परिवारजनों के साथ मकूर ग्राम की ओर रवाना हो गए। मकूर ग्राम का बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व है। 13, 14, 15 मई 1938 को उन्नाव जिले के मकूर ग्राम में जिला युवक संघ के तत्वावधान में प्रांतीय युवक सम्मेलन बुलाया गाय था। इसमें बाबा गुरूमुख सिंह (गदर पार्टी के 1915 के क्रान्तिकारी) मन्मथ नाथ गुप्त (काकोरी केस), यशपाल (वायसराय की गाड़ी बम से उड़ाने वाले), बटुकेश्वर दत्त (भगत सिंह के साथ असेम्बली में बम फेंकने वाले) ऐसे लगभग 150 क्रान्तिकारी आए थे। तीन दिनों तक मकूर ग्राम क्रान्तिकारियों की तीर्थस्थली बना रहा। इसमें त्रिपाठी जी ने नेताजी को आमंत्रित किया था क्योंकि उस समय वे ही ऐसे व्यक्ति थे जो भावी क्रान्ति की अगुवाई कर सकते थे। इन्हीं दिनों मकूर में ही सुभाष बाबु और त्रिपाठी जी ने फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना के निश्चय की घोषणा की। त्रिपाठी जी को उत्तर प्रदेश फारवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लॉक के मंत्री नियुक्त किया गया। श्री रामकृष्ण खत्री को उत्तर प्रदेश फारवर्ड ब्लॉक का मंत्री बनाया गया।

मकूर ग्रामवासियों को समाचार पत्रों से श्री देवब्रत बिश्वास के आगमन की सूचना मिल चुकी थी। ग्राम की सीमा तक वाहनों के पहुँचते ही वहाँ के नवयुवकों और वृद्धजनों ने – नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अमर रहें, पं. विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी अमर रहें – नारों से उनका स्वागत किया श्री बिश्वास ने मकूर की धरती को मनन करते हुए अनेक प्रसंगों को बताकर उद्बोधन किया। उन्होंने मकूर में नेताजी की मूर्ति लगवाने की भी घोषणा की।

श्री देवब्रत बिश्वास जी की इस आत्मीयतापूर्ण उन्नाव यात्रा ने इतिहास के अनेक पृष्ठ खोले।

.... श्रीमति रश्मि दीक्षित (सुपुत्री जननायक पं. विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी)

"हमारी सेवा का असली अधिकारी और हमारा सबसे अधिक पूज्य वह है, जो सबसे अधिक गरीब है"।

.... पं० विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी

"ताप-तप्त मरु में घन बनकर
शीतलता उपजाते हैं,
कुलिश-कुँज में भी अभंग,
जो गीत प्रेम का गाते हैं।
जीती है वसुधा उन वीरों की,
दी हुई सुधा पीकर -
अँधियाले में प्राण होमकर,
जो प्रकाश फैलाते हैं।"

... रामधारी सिंह 'दिनकर'

बिहार राज्य कमिटी - चुनावी घोषणा पत्र

मतदाता भाईयों एवं बहनों,

बिहार विधान सभा चुनाव 2010 आपके सामने है, जो छ: चरणों में 21 अक्तूबर से 20 नवम्बर 2010 तक होंगे। आने लालू-राबड़ी राज एवं नीतिश कुमार का कथित सुशासन भी देखा है। दोनों सरकारों में घोटाला महाघोटाला की फहरिस्त काफी लंबी है। सूबे की जनता ने लालू-राबड़ी राज के भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, चरमराती विधि व्यवस्था, अवसरवादी अनियता से तंग आकर नीतिश कुमार के नेतृत्व में संप्रग को सत्तासीन किया। लेकिन नीतिश कुमार की सरकार भी जनता के अरमानों को पूरा करने पाने में बुरी तरह विफल रही। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा की भूमिका बिहार में लूट का साझेदार की रही। वाम जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शक्तियां इस परिस्थिति में नहीं थी की इनके निरंकुश, मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगा सके। इसलिए विगत दो दशक बिहार भ्रष्टाचारियों, क्षुद्र जातपात की राजनीति का अभयारण्य बन गया, जिसमें अमर पसन्द लोगों, न्याय प्रिय लोगों की आवाज को नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गयी। नागनाथ की जगह सांपनाथ की बात चरितार्थ हो गयी।

महान देशभक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा संस्थापित राजनैतिक दल अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में विश्वास करती है। हमारा मानना है कि सत्ता परिवर्तन के जरिये जनता की बुनियादी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा

सकता है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने बिहार की भूमि रामगढ़ में अँग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वर्ष 1940 में ऐतिहासिक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित कर आजादी की लड़ाई का शंखनाद किया था लेकिन कांग्रेस की समझौता परस्त नीतियों के कारण नेताजी को देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। नेताजी ने भारत भूमि से बाहर जाकर तिसरी दुनिया की आजादी पसंद जनता को एकजुट कर समाजवादी भारत के निर्माण के लिए साम्राज्यवाद विरोधी समझौता विहीन संघर्ष को तेज करने के लिए आजाद हिन्द फौज एवं आजाद हिन्द सरकार का गठन किया जिससे भयभीत होकर अंग्रेजो को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन दूर्भाग्य है कि सत्ता लोलुप कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार कर सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को मंजूर किया जो सच्चे अर्थ में आजादी नहीं थी जिसका खामियाजा आज तक देशवासी भुगत रहे हैं।

सत्ता हस्तांतरण के छठे दशक के बाद भी सूबे में बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। बाढ़ जहां एक तरफ जनता के लिए तबाही रही वहीं भ्रष्ट नेताओं एवं भ्रष्ट नौकरशाहों के लिये वरदान रहा। बाढ़ एवं सुखाड़ के नाम पर अरबों की राशि पानी की तरह बहायी गयी। पूरी व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अनुबंध कर्मी चला रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। नौजवानाओं के साथ बेइंसाफी हो रही हैं।

70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। किसान खेती छोड़ रहे हैं। गांव से पलायन जारी है। बिहार की श्रम शक्ति से दूसरे राज्य में विकास का पहिया घूम रहा है। वहां पर हरियाली एवं रोशनी है लेकिन बिहार में बदहाली, बद्इंतजामी एवं अन्धेरा है। दूर दृष्टि राजनैथ्तक इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व के अभाव में बिहार आब गर्त में जा रहा है।

प्रदेश की 82 प्रतिशत आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। जिसके सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून आज तक नहीं बन पाया है। इस विशाल श्रम शक्ति को मुख्य धारा में लाये बिना हम कदापि अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी एवं स्लम एरिया में रहने वाले गरीबों के लिए सरकार के पास सोच का अभाव है। प्रदेश में अल्पसंख्यकों की हालात दयनीय है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से वे आज भी काफी पिछड़े है। उन्हें कभी "माई" समीकरण तो कभी कुछ का सब्ज बाग दिखाकर सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया।

सूबे में बेहतर शैक्षिक माहौल के अभाव में प्रतिभापलायन हो रहा है। शिक्षा माफिया को लाभ पहुँचाने के लिए शिक्षा का नीजिकरण एवं व्यवसायीकरण हो रहा है। आम आदमी शिक्षा एवं सवास्थ्य की पहुँच से बाहर है।

प्रदेश के कर्णधारों ने सामाजिक न्याय के नाम पर समाज के अंतिम व्यक्ति महादलित एवं अति पिछड़ा वर्ग को विकास का झुनझुना थमा दिया एवं सारी मलाई खुद खाने का काम किया, जिससे ये वंचित जमात अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है और सामाजिक मुख्य धारा से अलग थलग होकर सरकार एवं समाज के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक नया बिहार – एक खुशहाल बिहार बनाने के लिए नेताजी के विचारों एवं आदर्श पर संस्थापित अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की अगुयायी में व्यापक काम विकल्प का निर्माण करना अविार्य एवं परिहार्य है। अफसोस की बात हैं कि बिहार के वाम दल भी जनता की भावनाओं को सही रूप से परखने में विफल रहे। राष्ट्रीय स्तर पर लम्बे समय से साझा संघर्ष एवं कार्यक्रम के माध्यम से संगठित एवं स्थापित चार वाम दल भाकपा, भाकपा (मा), फारवर्ड ब्लॉक एवं आर.एस.पी. भी इस विधानसभा चुनाव में बड़े शरीक दलों की अदूरदर्शिता एवं सूझबुझ की कमी के कारण एकजुट नहीं हो सके। फारवर्ड ब्लॉक स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही वामपंथ का आधार मंच रहा है। फारवर्ड ब्लॉक प्रदेश में चार वाम दल सहित तमाम वामपंथी जनवादी धर्मनिरपेक्ष दलों, स्वतंत्र वाम संगठनों, वाम विचारों को एकजुट कर व्यापक एवं वृहत्तर वाम मोर्चा गठित करने का लगातार ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया लेकिन अपने निहित स्वार्थी तथा संकीर्णतावादी रूख के कारण वह वस्तुगत रूप से व्यापक वाम एकता के मार्ग में अवरोध बन गये। तमाम लम्बी चौड़ी घोषणाओं के बावजूद वाम एकता सही रूप से धरातल पर नहीं उतर पाया बल्कि लगभग एक तिहायी सीटों पर आपसी तालमेल भी नहीं हो पाया जो प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वामशक्तियों को इससे भ्रम एवं असमंजस की स्थिति बनी है। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई एवं जन–विकल्प निर्माण के मंसूबे को लेकर अपने संघर्ष एवं कार्यक्रम के साथ विधान सभा चुनाव मैदान में उतरा है।

ॐ नेताजी के सपनों का भारत के पुनर्निर्माण के संघर्ष को तेज करना।

ॐ व्यापक वाम एकता – बेहतर जन विकल्प को मजबूत करना।

ॐ महँगाई एवं भ्रष्टाचार पर लगाम – व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को तेज करना।

ॐ बाढ़ और सुखाड़ का स्थानी निदान।

ॐ गरीबी और अमीरी का अंतर मिटाकर समानता लाने।

ॐ किसानों की खुशहाली के बिना यह आजादी अधूरी है।

ॐ साम्पदायिकता जातिवाद को दूर भगाकर सामाजिक समरसना कायम करना।

ॐ बेकारी, भूख, भय, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी, अन्याय, शोषण विहीन समाजवादी भारत का पुनर्निर्माण।

ॐ असंगठित मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून – सालों भर काम की गारण्टी।

- ॐ देश एवं विदेशों में जमा कालेधन का पता लगाकर उसे जब्त करना।
- ॐ बंद पड़े तमाम कल-कारखानों को चालू कराने के लिए संघर्ष।
- ॐ प्रत्येक गरीब भूमिहीन परिवार को 10 डिस्मिल जमीन देना।
- ॐ भू-हदबंदी कानून एवं जनपक्षी भूमि सुधार कानूनों को सख्ती से लागु करना।
- ॐ शिक्षा एवं स्वास्थ्य के निजीकरण एवं व्यवसायिकरण पर लगाम।
- ॐ गरीब मंझोले किसान बटाईदारों को बिना सुद के सरकारी कर्ज, अनुदानित मूल्य पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयां, कृषि उपकरण बिजली, डीजल आदि मुहैया कराना।
- ॐ विधानसभा/लोकसभा में अति पिछड़ों को हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।
- ॐ विस्थापितों के पुनर्वास के लिए ठोस कानून का निर्माण। जल, जंगल एवं जमीन के अधिकार की रक्षा।

झारखण्ड उदय के 32 वर्षों के पश्चात् पहली बार पंचायत चुनाव

32 वर्षों के बाद झारखण्ड में पंचायत चुनाव कराये जाने की घोषणा की गयी है। चुनाव पाँच चरणों में कराये जायेंगे। 27 अक्तूबर 2010 को अधिसूचना जारी कर दी गई सूबे में 1978 ई० में अविभाजित बिहार के समय ही पंचायत चुनाव कराये गये थे। 15 नवम्बर 2000 ई० को भारत के राजनैतिक मानचित्र पर झारखण्ड राज्य का उदय हुआ था, तबसे लगातार राजनैतिक दलों, सामाजिक नागरिक संगठनों द्वारा प्रदेश के पंचायत चुनाव कराने की मांग पर दबाव डालने के लिए आन्दोलन जारी रहा। सड़क से संसद तक आवाज उठाीय गयी। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में दर्जनों याचिकायें दायर की गयी। अंत में 12 जनवरी 2010 को माननीय उच्च न्यायालय ने झारखण्ड सरकार को अविलंब पंचायत चुनाव कराने का निर्देश जारी किया। न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य में पेसा कानून के तहत चुनाव कराये जायेंगे, इससे राज्य के 72 प्रतिशत सदानों में आक्रोश उबल पड़ा है। पेसा कानून के तहत चुनाव होने से करीब 60 प्रतिशत पंचायतों एवं पंचायत समितियों में गैर आदिवासी मुखिया, प्रमुख या जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बन पायेंगे। सदानों ने न्यायालय एवं राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ 21 अक्तूबर 2010 को झारखण्ड बंद का आह्वान किया था। वामदलों ने राज्यपाल से मिलकर पेसा कानून के तहत दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा रही है। 32 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव कराने की घोषणा से राज्य में एक उत्सवी माहौल बन गया है। पंचायत चुनाव नहीं होने से जहाँ प्रदेश की भद्द पीट गयी थी वहीं प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के केन्द्रीय अनुदान से राज्य वंचित है।

- जनगर्जन संवादाता साथी जनार्दन पाण्डेय।

टी.यू.सी.सी. का छठवां दिल्ली राज्य सम्मेलन

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आदर्शों पर मजदूर वर्ग को संगठित करने वाले राष्ट्रीय श्रम महासंघ टी.यू.सी.सी., दिल्ली प्रदेश का सम्मेलन 31 अक्तूबर 2010 को जवाहर लाल नेहरू यूथ सेन्टर, 219, दिनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में होने जा रहा है। जिसका उद्घाटन टी.यू.सी.सी. राष्ट्रीय महासचिव साथी एस.पी. तिवारी जी करेंगे। दिल्ली प्रदेश राज्य महासचिव साथी पी.एन. द्विवेदी सम्मेलन की जानकारी देते हुये इसके महत्व को बताते हुये कहा-

आजादी के 63 वर्षो के बाद देश की मेहनतकश आवाम को साम्राज्यवाद और पूँजीवाद शोषण का शिकार बनी हुई है। असंगठित मजदूरों के लिये बने श्रम कानून अब तक कागज शेर ही साबित हुये है। मजदूरों द्वारा संघर्ष से अर्जित अधिकारों का देश के कोने-कोने में धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है व देश की राजधानी दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, नियमित कार्यावधि, सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से महफूज होना पड़ा है, इस परिस्थिति में मजदूरों को संगठित होकर अपने अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु संघर्ष का बिगुल बजाना ही होगा।

यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में हर रोज मजदूरों का अधिकार छीना जा रहा है। श्रम कानूनों का खुले तौर उल्लंघन हो रहा है। ऑर्डर, अवार्ड तथा जजमेन्ट काफी लम्बे अर्से तक श्रम आफिस में विलम्बित है। निर्माण कार्य के मजदूरों को जो कानून 1996 में बनाया गया आज तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया तथा उसमें मिलने वाली सुविधाओं से भी श्रमिक समुदाय वंचित है। दिल्ली को सुन्दरतम शहर बनाने के लिये विभिन्न राज्यों से आये हुये मजदूर वर्ग को तीन-तीन महीनें तक बिना किसी वेतन/देहाड़ी के मात्र दोनों वक्त के भोजन पर काम करने को मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य उत्पादन क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पुरानी गुलाम व्यवस्था की तर्ज पर मजदूरों का

लगातार शोषण कर रही हैं। दिल्ली सरकार एवं उसके अधिकारी गरीब मजदूरों की समस्याओं को सुनने को भी तैयार नहीं है।

टी.यू.सी.सी. के इस राज्य सम्मेलन के दौरान इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा के बाद आने वाले दिनों के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जायेगी।

टी.यू.सी.सी. की 11-12-13 दिसम्बर 2010 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले हम दिल्ली राज्य सम्मेलन कर रहे हैं। अत: आपसे अनुरोध है कि नेताजी के सपनों का भारत व मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिये इस सम्मेलन को सफल बनाने हेतु तन-मन-धन से सहयोग करें।

पश्चिम बंगाल स्टूडेण्ट्स ब्लॉक सम्मेलन साथी रमजान अली नगर में आयोजित

ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक का 28वां पश्चिम बंगाल राज्य सम्मेलन साथी रमजान अली नगर (कनकी, उत्तर दिनाजपुर) में 1, 2 व 3 अक्तूबर 2010 को विशाल जन रैली के साथ आयोजित हुई। जिसका उद्‌घाटन साथी देवब्रत बिश्वास, महासचिव अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने किया। साथी हाफिज आलम सैरानी, सचिव मण्डल सदस्य अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, साथी अक्षय ठाकुर, साथी अलि इमरान, अध्यक्ष ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक केन्द्रीय कमिटी, साथी देवब्रत रॉय, महासचिव ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक पश्चिम राज्य कमिटी ने भी रैली को सम्बोधित किया जिसकी अध्यक्षता साथी सूर्य दे ने की।

इस अवसर पर 'नेताजी मेला' का आयोजन भी किया गया और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष व बलिदान पर चित्रों की प्रदर्शनी भी की गयी। इसके कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

सम्मेलन हॉल में 5 युवतियों सहित 245 प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि सत्र के दौरान मंच का नाम शहीद खुदीराम बोस रखा गया। पूरे राज्यभर से प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और सभी ने शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया।

35 प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुये संगठन को बढ़ाने और उसके आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने मांग किया की प्रत्येक जिला में एक कॉलेज होना चाहिये। इसके अलावा बड़ी तादाद में रह रहे सीमा के नजदीक के छात्रों की समस्याओं को सुलझाने का भी मुद्दा उठाया। उर्दु और हिन्दी भाषी छात्रों के प्रति अमानवीय व उदासीन रवैये के प्रति सभी ने एक साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाये।

विस्तार पूर्वक चर्चा के पश्चात् 34 सदस्यीय नयी राज्य कमिटी बनाया गया, जिसमें 11 सचिव सदस्य थे। साथी विश्वजीत माइती और साथी सौम्यादीप सरकार क्रमश: अध्यक्ष और महासचिव नियुक्त किये गये।

साथी अमरेश कुमार, महासचिव ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक और साथी प्रकाश पाण्डेय, उपाध्यक्ष ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक भी सम्मेलन में उपस्थित थे तथा उन्होंने भी अपने-अपने वक्तव्य दिये।

साम्राज्यवाद का विरोध करने और नेताजी के सपनों का भारत बनाने के नारे का छात्रों को संदेश देते हुये साथी देवब्रत बिश्वास ने सम्मेलन का समापन किया।

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम का त्रि-देशीय सम्मेलन, 2-3 नवम्बर को आगरा में

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम तीनों देश की जनता के बीच मधुर एवं सुदृढ़ संबंध बनाने के उद्देश्य से किया गया। तीनों देशों की जनता के द्वारा एकसाथ मिलकर आवाज उठाने का यह एकमात्र मंच है। बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम् (बी.बी.पी.पी.एफ.) 2-3 नवम्बर 2010 को आगरा, उत्तर प्रदेश में त्रि-देशीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। जिसमें तिनों देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा इस संगठन की महिला समिति की भी विशेष सभा का आयोजन इसी अवधि में आयोजित होगी।

अग्रगामी महीला समिति की राष्ट्रीय सम्मेलन की आरंभिक

तैयारी तेज

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति की प्राथमिक कमिटी की मीटिंग कोलकाता के हेमन्ता बसु भवन, 49 सी, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता में 23 अक्तूबर 2010 को हुई। जिसकी अध्यक्षता साथी शिखा सेनगुप्ता ने की। मीटिंग मुख्य रूप से साथी अशोक घोष, साथी देवब्रत बिश्वास, साथी डॉ. बरूण मुखर्जी, साथी अपर्णा सेनगुप्ता, साथी हरीपद बिश्वास, साथी मोइनुद्दीन शम्स और साथी देवब्रत रॉय भी उपस्थित थे।

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति की 4-6 दिसम्बर को कोलकाता में होने वाली तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की आरंभिक कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गयी और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

1. पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जायेगा, अभी तक 98000 सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। यह संख्या नवम्बर के अंत तक 1,75000 को पार करनी है। इस प्रकार की सदस्यता अभियान अन्य राज्यों में भी राज्य के पार्टी नेताओं के निर्देशानुसार चलाना है।

2. खुला अधिवेशन में महिला श्रोताओं की संख्या, पश्चिम बंगाल की जिला महिला समिति नेताओं ने अभी तक 25,140 निर्धारित की है जिसे अन्य राज्यों से भी महिला प्रतिनिधियों को आमन्त्रित कर 50,000 तक करना है।

3. (क) खुला अधिवेशन 4 दिसम्बर को रानी रासमनी रोड़, कोलकाता में दोपहर 12 बजे होगा।

(ख) पहला प्रतिनिधि सत्र उसी दिन पंजीकरण कार्यों के पश्चात् 6.00 सायं को साल्ट लेक स्टेडियम में होगा। प्रतिनिधि सत्र में सम्मेलन का राजनैतिक मसौदा प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) 5 दिसम्बर 2010 को सुबह का सत्र 10 बजे से आरम्भ होगा, जिसमें विदेश से आये प्रतिनिधि और हमारे वैचारिक मित्र संगठन सीपीआई (एम), सीपीआई और आरएसपी के प्रतिनिधि अपना-अपना वक्तव्य रखेंगे।

(घ) दूसरो और तीसरा प्रतिनिधि सत्र दोपहर के भोजन के पश्चात् आयोजित होगा।

(ङ) चौथा और अंतिम प्रतिनिधि सत्र 6 दिसम्बर 2010 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य में होगा।

4. विदेशी प्रतिनिधि हमारे पड़ोसी मुल्कों जैसे - बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालद्वीव और नेपाल से आमंत्रित किये जायेंगे।

5. सम्मेलन हेतु वित्त की व्यवस्था के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा जिसमें डोर-टु-डोर जाकर विज्ञापन और कूपन के जरिये की जायेगी। अन्य राज्यों के लिये विज्ञापन और कूपन हिन्दी और अँग्रेजी में भी छपी है।

6. पोस्टर की छपाई का कार्य 3 नवम्बर 2010 तक पूरा करके नई दिल्ली अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की मीटिंग में वितरित कर दिया जायेगा।

8. प्रतिनिधि फी 50 रुपये होगी।

9. सम्मेलन में 300 सदस्यीय महिला प्रतिनिधियों का राज्यवार कोटा इस प्रकार है:

(क) पश्चिम बंगाल -150, आसाम-10, त्रिपुरा-5, मणिपुर-2, उड़ीसा-5, नागालैण्ड-2, झारखण्ड-20, बिहार-10, उत्तर प्रदेश-10, मध्य प्रदेश-10, दिल्ली-10, केरल-5, तमिलनाडु-5, कर्नाटक-10, जम्मू और कश्मीर-5, पुदूचैरी-2, महाराष्ट्र-10, आन्ध्र प्रदेश-2, उत्तराखण्ड-2, पंजाब-2।

(ख) प्रतिनिधियों का नाम जिला स्तरीय सम्मेलन के पश्चात् निर्धारित किये जाये। जिला सम्मेलन के न होने पर प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. (क) आजादी के संघर्ष में महिलाओं के योगदान पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कोलकाता के मेट्रो चैनल (एस्पलानेड) में 1 दिसम्बर से 6 दिसम्बर 2010 तक लगाया जायेगा। प्रदर्शनी मंच का नाम क्रांतिकारी नेता श्रीमती प्रीतिलता वादेदर (1911-1932) के नाम रखा जायेगा, जिनका जन्म शताब्दी समारोह 2011 में मनाया जायेगा।

(ख) प्रतिनिधि सत्र मंच का नाम क्रांतिकारी श्रीमति बिना दास (भौमिक) (1911-1986) होगा।

(ग) सम्मेलन स्थल का नाम फारवर्ड ब्लॉक की नेता और क्रांतिकारी सुभाष चन्द्र बोस से जुड़ी श्रीमति लीला रॉय (1900-1970) होगा।

10. राष्ट्रीय सम्मेलन पर एक पत्रिका का प्रकाशन होगा।

11. 'महिला अधिकार के 100 वर्ष' का सम्मेलन में अनुष्ठान किया जायेगा।

12. (क) योग्य एवं समर्पित 100 स्वयंसेवकों की भर्ती की जायेगी। इन स्वयंसेवकों में महिला एवं पुरूष दोनों होंगे।

(ख) 15 मार्ग दर्शक नियुक्त किये जायेंगे जो विदेशी और देशी मेहमानों को लाने और जाने का कार्य देखेंगे तथा उनके यातायात का ध्यान रखेंगे।

13. पार्टी की कोलकाता जिला कमिटी 4 दिसम्बर 2010 को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रतिनिधियों के स्वागत और खुला अधिवेशन को पूरा करेगा।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें : शिखा सेनगुप्ता, हेमन्ता बसु भवन, 49 सी, चित्तरंजन एवेन्यु, कोलकाता-700012,

फोन: +91-33-22373956/1943